

भारत सरकार  
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  
(खेल विभाग)  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1472  
उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026  
20 माघ, 1947 (शक)  
खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन

**1472. श्री मलविंदर सिंह कंग:**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 'खेलो इंडिया' योजना के 'खेल बुनियादी ढांचे के सृजन और उन्नयन' घटक के तहत पंजाब राज्य को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्ष - वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के तहत पंजाब के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के लिए स्वीकृत खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती है और खेल में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को रोजगार या शैक्षिक प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु पंजाब राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो केंद्रीय और राज्य की पहलों के एकीकरण के माध्यम से पंजाब द्वारा प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है जिनमें उन खिलाड़ियों की संख्या भी शामिल है जिन्हें केंद्र सरकार के सहयोग से नौकरी या शैक्षिक लाभ प्राप्त हुआ है?

उत्तर  
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री  
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) इस मंत्रालय में धनराशि राज्य-वार या घटक-वार नहीं, स्कीम-वार जारी की जाती है। विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पंजाब राज्य सहित देशभर में खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत खेल अवसंरचना और विकास परियोजनाओं के लिए जारी धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत जारी धनराशि
2022-23	596.39

2023-24	872.20
2024-25	620.75
2025-26	628.91 (दिनांक 15.01.2026 की स्थिति के अनुसार)

(ख) पंजाब राज्य सहित देशभर में खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत इसके प्रारंभ से स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण जिसमें खेल परिसरों और उनकी स्वीकृत लागत, जारी धनराशि और इसकी वास्तविक और वित्तीय प्रगति शामिल है, मंत्रालय के डैशबोर्ड <https://mdsd.kheloindia.gov.in> पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ग) और (घ): युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अपनी विभिन्न खेल विकास स्कीमों की प्रगति और कार्यान्वयन की नियमित निगरानी बहु-स्तरीय पर्यवेक्षण तंत्र के माध्यम से करता है। इस प्रक्रिया में नियतकालिक प्रदर्शन समीक्षा, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा स्थल निरीक्षण शामिल हैं ताकि धनराशि का कुशल उपयोग और खेलो इंडिया स्कीम एवं अन्य प्रमुख पहलों के अंतर्गत परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को रोजगार अथवा शैक्षणिक प्रोत्साहन प्रदान कर खेलों में युवाओं को भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करने सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का होता है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय पंजाब राज्य सहित देश में खेलों के विकास हेतु निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है:

- (i) खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
- (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;
- (iii) अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को नकद प्रोत्साहन;
- (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
- (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
- (vi) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
- (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि;
- (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; और
- (ix) राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर)।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

पंजाब राज्य से पैरा ओलंपिक श्रेणी में भारोत्तोलन विधा के लिए एक कोच को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, पंजाब राज्य में अधिसूचित 29 खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) में 30 पूर्व चैंपियन एथलीट (पीसीए) विभिन्न खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

\*\*\*\*\*